(ग) संसद सदस्यों के कोटे के लिए निर्धारित धनराशि कब तक जिला कलेक्टरों को भेज दी जायेगी?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमैंग): (क) लोकसभा के सभी सदस्यों (लोकसभा में नामित दो संसद सदस्यों को छोड़कर) को संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत प्रति सांसद 50 लाख रू० की प्रथम किस्त को पहले ही जारी कर दिया गया है। राज्य सभा के उन 22 सांसदों जिन्होंने अपने विकल्प दिए थे, के बारे में भी धनराशि जारी की जा चुकी है। राज्य सभा के 74 सांसदों जिनके विकल्प जुलाई, 95 मास के अन्त तक प्राप्त हुए थे, को धनराशि शीघ्र ही जारी की जा रही है।

(ख) चूंकि राज्य सभा के कुछ सांसदों ने अपने विकल्प नहीं दिए हैं अतः वर्ष 1995-96 के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत उनसे सम्बद्ध धनराशि को जारी करने का कार्य पूरा नहीं किया गया है।

(ग) राज्य सभा सांसदों से वर्ष 1995-96 के लिए उनके विकल्प प्राप्त होने पर ही धनराशि को जारी किया जा सकता है।

Cooperative sector in Sugar Production

773. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether there is any proposal for providing assistance to Cooperative Sector for sugar production;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the specific steps proposed to encourage the cooperative sector to enter the sugar sector?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) to (c) As per the licensing policy guidelines announced by the Government of India vide Press Note No. 16 (1991) series dated 8.11.91, other things being equal preference in licensing is to be given to proposals from the cooperative sector over the public and private sector.

Assistance is also provided for cane development and modernisation.

भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्यातकों को चावल की आपूर्ति किए जाने में विलम्ब

774. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी:**
श्री जनेश्वर मिश्र:

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल निर्यातकों को चावल की आपूर्ति में विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने किन बंदरगाहों पर चावल के निर्यात की व्यवस्था की है; और

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम निजी निर्यातकों के माध्यम से चावल की आपूर्ति किए जाने का आग्रह करता रहा है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) भारतीय खाद्य निगम की ओर से अपनी खुले बाजार की बिक्री की योजना के अधीन निर्यात के प्रयोजन के लिए चावल के प्रत्याशित खरीदारों को चावल रिलीज करने में किसी प्रकार विलम्ब नहीं हुआ है। तथापि, जहां पर रेल-संचलन होता है वहां पर कुछ विलम्ब हुआ है। यह विलम्ब स्टाक के संचलन हेतु उन स्टेशनों पर रेलवे वैगनों की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण हुआ है जहां क्रेताओं द्वारा चावल का निरीक्षण किया गया है और इसे स्वीकार किया गया है। इसके अलावा उनके द्वारा वांछित स्थानों पर भी विलम्ब हुआ है।

(ख) चूंकि फिलहाल, भारतीय खाद्य निगम चावल का सीधे निर्यात नहीं कर रही है इसलिए इसे पत्तनों पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं करनी है।

(ग) जी, नहीं।

गरीबी में बढ़ोतरी

775. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 जून, 1995 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "पावर्टी राइजिंग बाई टू परसेन्ट इनुअली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर मिलाया गया है;

434-405-E3A